[Dr. Vasant Kumar Pandit]

pile coal and coke in every State and. then the States would at a very short notice either through road transport or other methods of transport move the coal to the required industries, to the required thermal power stations, industries and even to consumers whose requirement of coal is low.

This crisis, therefore, has given warning to the Government about it. Whatever may be the reason due to this crisis a stituation like this should not arise in the coming future. A coordination body consisting of 3-4 depratments should be set up immediately so that this problem can be solved. Otherwise this crisis may bring an economic recession as far as coming three months are concerned. I would like to draw the attention of the house to the fact that the coming months are the peak consumption period for the requirement of electricity. During these three months the stock in the thermal power stations and the industry should be as high as possible. Therefore I would call upon the Government to come forward and publicly allay our fears by working out exactly what arrangement has been made as far as movement of coal is concerned— how much coal is available ; how many wagons are available ? As far as public is concerned the public should be assured that coal will be available within the next 10-15 days, coal will be available to every consumer on priority basis as expeditiously as possible.

सभापति महोदय : श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ;

श्री भगत राम (फिलौर) : पंजाब में भी कोयले के संकट के कारण भट्टे बन्द पड़े हैं। वहां पर कोयला नहीं मिल रहा है और भट्टे बन्द होने के कारण लाखों मजदूर बेकार हो रहे हैं। मैं इस के बारे में कई दफा कह चुका हूं कि लेकिन अभी तक मेरा नोटिस एडमिट नहीं हुआ है। बहुत से मजदूर बेकार हो गये हैं और पंजाब में इस के कारण बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है।

सभापति महोदय अभी आप का का नोटिस एडमिट नहीं हुआ है, आप बैठ जाइए।

(iii) DIFFICULTIES FOR COLD-STORAGE OF POTATOES IN UTTAR PRADESH

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (कन्नोज) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की आवाज इस माननीय सदन में पहुंचाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के विशेषकर उस हिस्से उत्तर प्रदेश के दो, तीन जिले फारुखाबाद, कानपुर और इटावा, जहां पर शायद इस सम्पूर्ण देश में सब से अधिक आलू वहां के किसान पैदा करते हैं—वहां के किसानों के साथ जो इस समय अन्याय हो रहा है, उस की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह समस्या इतनी गम्भीर थी कि मैं ने इस के लिए एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया था परन्तु नियम 377 के अन्तर्गत मुझे इस मामले को उठाने की आज्ञा मिली है। इस समस्या का कैसे समाधान होगा ? इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आ रही है।

सभापति महोदय अब कहानी मत कहिये, अपनी बात ही कहिये, स्टेटमेंट ही पढ़ दें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहानी यह है कि एक मनिहार अपने सिर पर चूड़ियों का ढेर ले जा रहा था। दो तीन आदमी उस की तरफ दौड़े और उन्होंने उस के सिर पर एक लठ मारा और पूछा कि इस में क्या है उसने कहा कि एक लठ और मारो और फिर पूछो कि इसमें क्या है ताकि जो कुछ रह गया है वह भी टूट जाए। लाखों, करोड़ों रुपये के आलुओं के बोरों का ढेर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और शीतगृह वाले उस को अपने यहां नहीं रख रहे हैं। उन के संघ ने यह फैसला कर लिया है कि हम किसानों का आलू नहीं रखेंगे और स्वयं सस्ता आलू खरीद कर उन शीतगृहों में रख रहे हैं। 20 रुपये क्वींटल का रेट उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा

था लेकिन वह उन को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यह ज्यादती की है कि जहां पिछले साल 8 रुपये क्वींटल के हिसाब से आलू रखा गया था, वहां उन्होंने इस साल 13 रुपये क्वींटल का रेट तय कर दिया है लेकिन इस के बाद भी शीतगृह के मालिक लोग प्रसन्न नहीं हैं। किसानों की बैलगाड़ियां शीतगृहों के सामने खड़ी हैं और पुलिस की मदद से डंडे मार मार कर किसानों को वहां से हटाया जा रहा है और स्वयं अपने पैसे से आलू खरीद कर ट्रक के ट्रक शीतगृहों में भरे जा रहे हैं। इस तरह से वहां पर किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। जिला प्रशासन से कहा गया। जिला प्रशासन से जो अधिकारी वहां पर भेजे गये, तो होली की छुट्टी पड़ जाने के कारण दो दिन का मौका और उन्होंने दे दिया जिस के कारण शीतगृहों के मालिकों ने किसानों से सस्ते दामों पर आलू लेकर भर लिये ताकि वे अच्छा मुनाफा कमा लें। एक और षड्यंत्र वहां पर चल रहा है कि प्रदेश के बाहर आलू का जाना बिल्कुल बन्द कर दिया, उस का लदान बिल्कुल बन्द हो गया और वैगनों की कमी बताई गई। इस तरह से और भी दूसरी चीजें हैं जिन की वजह से ऐसी हालत वहां पर पैदा हो गई है। इसलिये मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक तो ओलों के कारण आलू खराब हो गये और इससे किसान मर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में यह तमाशा चल रहा है कि मंत्री जी कहते हैं कि हम ने लगान माफ कर दिया लेकिन लगान छः गुना लगा दिया गया। इससे किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। हम चिल्लाते है कि अब तो किसान का बेटा गद्दी पर बैठा गया है और किसानों की हालत सुधरेगी लेकिन दूसरी ओर किसान इस तरह से लुटते जा रहे हैं।

इसलिए मैं नियम 377 के अन्तर्गत भारत सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कर रहा हूँ।

(IV) REPORTED STRIKE IN DURGAPUR FERTILIZER FACTORY

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan) : Mr Chairman Sir, our country is mainly based on agriculture. The whole economy of our country depends mainly on agricultural production. Fertiliser is an essential commodity to produce crops. Sometimes not only food but also industrial-crop production is being hampered in our country due to shortage of fertilisers. The production in the Durgapur Fertiliser Factory of the Fertiliser Corporation of India only some days back had been completely stopped due to general workers' strike.

Now the technical supervisors of the Durgapur Fertiliser Factory of the Fertiliser Corporation of India will go on mass casual leave on March 31 in protest against the Corporation's policy of pursuing 'double standards in respect of status and pay structure for technical officers'. The supervisors have already begun an indefinite relay hunger strike on 26th March, 1978. If this threat materialises, the country would have to suffer a huge loss and the whole cultivation works will be severely hampered again.

Therefore, I would like to draw the attention of the Minister-in-charge to this and request that he should take this matter seriously and come out with a statement setting forth the steps taken by the Government to prevent the hunger strike and to fulfil the demands of those officers. Government should take immediate action in the matter to meet the demands of the officers and to avoid the stoppage of production of fertiliser which is a very important product for our people and for our industry.

SHRI SOMNATH CHATTERJI (Jadavpur) : Now, on political grounds the locations of offices of government undertakings are being fixed. This is a very serious matter. The office of the Fertiliser Corporation is being shifted from Calcutta.

AN HON. MEMBER : The MPs of West Bengal have submitted a joint representation to the Minister (*interruptions*).